



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3— Sub-section 'i'

प्राधिकरण से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63]  
No. 63]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1988/माघ 19, 1909  
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1988/MAGHA 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ रख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

विदेशी कर प्रभाग

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1988

अधिसूचना न 7754

आय-कर

सा. का नि 80(अ) — आय पर कर की वापस  
दोहरे कराधान से बचने और राजस्वीय अपबन्धन को रोकने  
के लिए भारत गणराज्य की सरकार और हमानिया ममाज-

वादी गणराज्य की सरकार के बीच इससे मलगम अभिसमय  
14 नवम्बर, 1987 को उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 31 के  
पैरा 1 की अवेक्षानुसार दोता मविदाकारी राश्यों द्वारा अनु-  
समर्थन की लिखन का आवाहन प्रदान किए जाने पर, प्रवृत्त  
हुआ है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961  
(1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ)  
अतिकर अधिनियम 1964 (1964 का 7) की धारा 24क  
द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती  
है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबन्धों को भारत मघ  
में कार्यान्वित किया जाए।

## उपाबंध

आय पर करा के  
संबंध में  
दोहरे कराधान के परिहार और  
राजस्व अपवंचन को रोकने  
के लिए  
भारतीय गणराज्य की सरकार  
और  
रुमानिया समाजवादी गणराज्य की सरकार  
के बीच  
अभिसमय

भारतीय गणराज्य की सरकार और रुमानिया समाजवादी गणराज्य की सरकार आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए और अधिकारों की समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने के लिए एक अभिसमय करने की इच्छा में,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है—

## अनुच्छेद 1

## वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

## अनुच्छेद 2

1 यह अभिसमय जिन करों पर लागू होगा वे हैं—

(क) भारत के मामले में :

- (1) आयकर और उस पर कोई भी अधिभार;  
और
- (2) अतिकर;  
(जिन्हें इसके बाद “भारतीय कर” कहा गया है)।

(ख) रुमानिया के मामले में :

- (1) व्यष्टियों और निगमित निकायों द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय पर कर;
- (2) रुमानिया के कुछ आर्थिक संगठनों और कुछ विदेशी सहभागियों की सहभागिता में गठित संयुक्त कम्पनियों के लाभों पर कर, और
- (3) कृषि-कार्यकलापो में प्राप्त आय पर कर,  
(जिन्हें इसके बाद “रुमानिया का कर” कहा गया है)।

2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी प्रकार के उन करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए गए हों।

3. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में, जो इस अभिसमय के विषय हैं, किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे और संगत अधिनियमों और विनियमों की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।

## अनुच्छेद 3

## सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

(क) “भारत” शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र और उसमें शामिल है राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का आकाशी क्षेत्र तथा कोई भी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र, जिस पर भारतीय कानून के अनुसार और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के सार्वभौम अधिकार, अन्य अधिकार और श्रेताधिकार हों;

(ख) भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त “रुमानिया” शब्द का अभिप्राय रुमानिया समाजवादी गणराज्य का राज्यक्षेत्र है, जिसमें रुमानिया का राज्यक्षेत्रीय समुद्र और महाद्विपीय मग्नतट और रुमानिया के राज्यक्षेत्रीय मागर-खण्ड से आगे कोई ऐसा अन्य क्षेत्र शामिल है जहां रुमानिया समुद्र, जल, समुद्र-तल तथा इन सागर-खण्डों में विद्यमान प्राकृतिक, जैविक और खनिज संसाधनों की खोज और उपयोग में संबंधित अन्तरराष्ट्रीय कानून और अपने निजी कानून के अनुसार सार्वभौम अधिकारों का प्रयोग करता हो;

(ग) “एक संविदाकारी राज्य” और “दूसरे संविदाकारी राज्य” शब्दों में, सन्दर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारत अथवा रुमानिया अभिप्रेत है,

(घ) “कर” शब्द में, सन्दर्भ की अपेक्षानुसार, भारतीय कर अथवा रुमानिया का कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में ऐसी चूक अथवा भूल के संबंध में देय हो, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थवण्ड के रूप में हो,

(ङ) “व्यक्ति” शब्द का अर्थ वह होगा जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रचलित कराधान कानूनों में उसका अर्थ है;

(च) "कम्पनी" शब्द में अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय, जिसमें वह संयुक्त कम्पनी शामिल है, जो रूमानिया के कानून के अन्तर्गत अन्तर्निगमित की गयी हो अथवा कोई ऐसी सन्ता जिने संबंधित संविदाकारी राज्यों के कगधान कानूनों के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में माना जाता हो;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(ज) "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों से, भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केन्द्रीय सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और रूमानिया के मामले में वित्त मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अभिप्रेत है ;

(झ) "राष्ट्रिक" शब्द में अभिप्रेत है :

—भारत के मामले में, भारत की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी ऐसा विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था, जो भारत में प्रचलित कानूनों से अपनी यह हैसियत प्राप्त करते हो;

—रूमानिया के मामले में, रूमानिया की नागरिकता धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी ऐसा विधिक व्यक्ति, भागीदारी या संस्था जो रूमानिया में प्रचलित कानूनों से अपनी यह हैसियत प्राप्त करते हो ;

(ञ) "कोई राजनीतिक उप-प्रभाग" शब्द से भारत में कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अभिप्रेत है;

(ट) "प्रशासनिक राज्यक्षेत्रीय इकाई" शब्द से रूमानिया में प्रशासनिक राज्य-क्षेत्रीय इकाई अभिप्रेत है,

(ठ) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" शब्द में किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन अभिप्रेत है, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, निवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य के ही स्थानों के बीच चलाया जाता हो ।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय को लागू करने में किसी भी पद का, जो इसमें परिभाषित नहीं हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो उस राज्य में प्रवृत्त उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस अभिसमय के विषय हैं ।

## अनुच्छेद 4

### आर्थिक अधिवास

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों में अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य के कगधान कानूनों के अनुसार उस राज्य का निवासी हो ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंध के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, वहां इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ उसकी निवासीय हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी :—

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसका एक स्थायी निवास-गृह हो । यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक सम्बन्ध घनिष्ठतर है (इसके बाद उसके "महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" के रूप में उल्लिखित) ;

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास-गृह नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

(ग) यदि वह आवतन सामान्य दोनों की संविदाकारी राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में आवतन नहीं रहता हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों ही संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति में इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित हो ।

## अनुच्छेद 5

### स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए, "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहां से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दों में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :—

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शान्ता;
- (ग) कोई कार्यालय,
- (घ) कोई कारखाना,
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस-कूप, खदान अथवा कोई अन्य स्थान, जहाँ से प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हों;
- (छ) दूसरों के लिए भण्डारण की सुविधाएँ प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति का कोई मालगोदाम;
- (ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान, जहाँ कृषि बनोद्योग, बागान अथवा संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों;
- (झ) कोई परिसर, जिसका प्रयोग विक्रय-स्थल या आदेश प्राप्त करने अथवा मंगवाने के लिए किया जाता हो;
- (ञ) कोई प्रतिष्ठान अथवा सरचना, जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता हो;
- (ट) कोई भवन स्थल अथवा निर्माण, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन-परियोजना अथवा तत्संबंधी पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जहाँ ऐसा स्थल, परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्य-कलाप (अन्य ऐसे स्थान, परियोजनाओं या कार्य-कलापों सहित, यदि कोई हो) छ. महीनों से अधिक की अवधि के लिए चालू रहते हों, अथवा जहाँ ऐसी परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जो मशीनरी अथवा उपकरण की बिक्री के लिए प्रासंगिक होने के कारण, छ. माह से अधिक अवधि के लिए चालू नहीं रहते हो और परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए वेय प्रभार मशीनरी या उपकरण के विक्रय-मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :—

- (क) उद्यम के माल अथवा तिजारती माल के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा तिजारती माल का स्टॉक रखना;

(ग) अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा तिजारती माल का स्टॉक रखना;

(घ) उद्यम के लिए, माल अथवा तिजारती माल का केवल ऋय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;

(ङ) उद्यम के लिए, अनन्य रूप से विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान, अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में, जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;

(च) यदाकदा आयोजित किए जाने वाले अस्थायी मेले या प्रदर्शनी में प्रदर्शित उद्यम के माल अथवा तिजारती माल को इस प्रकार के मेले अथवा प्रदर्शनी को समाप्त करने की प्रक्रिया में बेचना;

(छ) मशीनरी अथवा उपकरण के विक्रेता से भिन्न किसी उद्यम द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना या पर्यवेक्षी कार्यकलाप, जो मशीनरी अथवा उपकरण की बिक्री के लिए प्रासंगिक है और छ. माह से अधिक अवधि के लिए चालू नहीं रहते हैं।

तथापि, उप पैराग्राफ (क) से (छ) तक के उपबंध वहाँ लागू नहीं होंगे, जहाँ उद्यम उक्त उप-पैराग्राफों में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यापार का कोई भी अन्य निर्धारित स्थान रखता हो।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहाँ किसी स्वतंत्र हैसियत के अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है, एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि :

(क) उसे, उस राज्य में उद्यम की ओर से संविदा सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह प्रायः उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा तिजारती वस्तुएँ खरीदने तक ही सीमित नहीं हो;

(ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार न हो, परन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रायः माल अथवा तिजारती वस्तुओं का स्टॉक रखता हो, जिससे से वह उद्यम की ओर से माल अथवा तिजारती वस्तुओं की नियमित रूप से डिस्चार्ज करता हो; अथवा

(ग) वह प्रयोजित राज्य में समग्रतः प्रथम लक्ष्य समग्रतः स्वयं उस उद्यम के लिए ही अथवा उस उद्यम तथा अन्य उद्यमों के लिए आदेश प्राप्त करता हो, जो उस उद्यम को नियन्त्रित करने हो अथवा उसने नियन्त्रित होते हो अथवा उसी प्रकार के सामान्य नियन्त्रण में आने हो जिसमें कि वह उद्यम आता है।

5 एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे सविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण स्थायी स्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन अभिकर्ता अथवा स्वतंत्र हैमियन वाले किसी अन्य अभिकर्ता के माध्यम से कारोबार करता है बशर्ते कि ऐसी व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप में कर रहे हो। किन्तु, जब ऐसे एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से किए जाते हो जो उस उद्यम को नियन्त्रित करने ह उस उद्यम द्वारा नियन्त्रित होते ह अथवा उसी प्रकार के सामान्य नियन्त्रण के अधीन हो जैसा कि उक्त उद्यम, तो उस उद्यम स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत एक स्वतंत्र हैमियन का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

6 इस तथ्य से कि कोई कंपनी, जो एक सविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियन्त्रित करती है अथवा उससे नियन्त्रित होती है, जो दूसरे सविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे सविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, इन दोनों कंपनियों में से कोई भी अपने आप एक दूसरे का स्थायी स्थापन नहीं बनायीं।

#### अनुच्छेद 6

##### अचल सम्पत्ति में आय

1 अचल सम्पत्ति में आय पर केवल उस सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो।

2 अचल सम्पत्ति" शब्दों का उस सविदाकारी राज्य के कानून और प्रथा के अनुसार परिभाषित किया जाएगा, जिसमें वह सम्पत्ति स्थित है। इस शब्द में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि, और वनोद्योग में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हो अचल सम्पत्ति का भोगने के अधिकार और खनिज भंडार तेल कूपा, खदान और प्राकृतिक समाधनों को निकालने के अन्य स्थानों के संचालन के लिए अथवा संचालन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अवधिगियों के अधिकार। जलयान और वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3 पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उस किए गए पर दन अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4 पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

#### अनुच्छेद 7

##### कारबार में लाभ

1 एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उन्हीं राज्य में कर लगाया जाएगा जहां तक कि वह उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से उसमें कारबार नहीं करता हो। यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारबार करता हो तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, किन्तु केवल उन्ने अंश पर ही कर लगेगा जो (क) उस स्थायी स्थापन, (ख) उस दूसरे राज्य में उन्हीं अथवा उन्हीं प्रकार के माल अथवा तिजारती वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त हुआ माना जा सकता हो जैसी कि उस स्थायी स्थापन के माध्यम से बिक्री जाती हो, अथवा (ग) उस दूसरे राज्य में किए जा रहे वैसे ही अथवा उन्हीं प्रकार के व्यापारिक कार्यकलापों से प्राप्त हुआ माना जा सकता हो जो उस स्थायी स्थापन के माध्यम से किए जाते हो।

2 पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां एक सविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक सविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी स्थापन का ही लाभ समझा जाएगा जिसे वह उस स्थिति में प्राप्त करने की अपेक्षा करता जब वह उन्हीं या वैसे ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारबार करता, जिसका वह स्थायी स्थापन है। किसी भी स्थिति में, जहां किसी स्थायी स्थापन को प्राप्त हुआ समझा जा सकेने योग्य लाभ निश्चित नहीं किया जा सकता हो अथवा उसे निश्चित करने में असाधारण कठिनाइयां उत्पन्न होती हो, वहां स्थायी स्थापन को प्राप्त हुए समझे जा सकने योग्य लाभों के अनुमान युक्तियों का आधार पर लगाया जा सकता है।

3 किसी स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्यय को कटौतियां के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी स्थापन के कारणार परंप्रजाता में किए जाते हैं, जिसमें इन प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल ह जो उ। राज्य के कराधान कानूनों के उपबन्धों के अनुसार हो, फिर चाहे वे उस राज्य में किए गए हो, जहां स्थायी स्थापन स्थित है, अथवा अन्यत्र। किन्तु इस प्रकार की कोई कटौती उन रकमों, यदि कोई हो, के



संबंध में स्वीकार नहीं की जाएगी जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यव की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), रायल्टियों, फीसों अथवा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले की गई अन्य इसी प्रकार की अदायगियों, अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में की गई हों, अथवा जो बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में अदा की गई हों। इसी प्रकार स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन रकमों को हिसाब में नहीं किया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को, रायल्टियों, फीसों अथवा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले की गई ऐसी ही अन्य अदायगियों अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के रूप में अदा भी की गई हों अथवा जो बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके कार्यालयों में से किसी अन्य कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यव की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) प्रभारित की गई हों।

4. कोई लाभ मात्र इस कारण स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा तिजारती वस्तुएं खरीदी जाती हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए स्थायी संस्थापन को हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक उसके लिए कोई ठीक तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारण नहीं हो।

6. जहां आय में लाभों की वे मंजूर शामिल हों, जिन पर इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे।

#### अनुच्छेद 8.

##### विमान परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध किसी पूल, किसी संयुक्त कारवार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे विमान के परिचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और ऐसे ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 12 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

4. "विमान परिचालन" शब्दों का अर्थ होगा विमान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा प्रवक्ताओं (चार्टरर्स) द्वारा यात्रियों, डाक पशुधन या माल का विमान द्वारा परिवहन का कारवार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का आकस्मिक पट्टा और ऐसे परिवहन में प्रत्यक्षतः संबंधित कोई भी अन्य कार्यकलाप शामिल हैं।

#### अनुच्छेद 9

##### जहाजरानी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से अर्जित लाभों पर केवल उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा।

2. पैरा 1 के उपबन्धों के होने हुए भी, यदि अन्तरराष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से संबंधित क्रियाकलाप उम दूसरे राज्य में किए जाने हों तो ऐसे लाभों पर उम दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जाएगा, लेकिन इस प्रकार लगाया जाने वाला कर उम दूसरे राज्य में पोतों के संचालन के संबंध में संदेय सकल राशि के 2.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध किसी, पूल, संयुक्त कारवार अथवा पोत संचालन में सभी किसी अन्तरराष्ट्रीय पोत संचालन एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, एक संविदाकारी राज्य में पोतों के संचालन के संबंध में संदेय सकल राशि का अर्थ होगा निम्नलिखित राशियों का कुल योग, अर्थात्:—

(क) उस संविदाकारी राज्य में किसी बन्दरगाह अथवा बंदरगाह पर यात्रियों, पशुधन-डाक या माल को पोतों से लाने-ले-जाने के कारण संदेय सकल राशि;

(ख) उस संविदाकारी राज्य में अन्तरराष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से संबंधित निधियों पर प्राप्त होने वाला ब्याज; और

(ग) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल या तिजारती वस्तुओं के परिवहन के संबंध में कन्टेनर्स (जिसमें ट्रैलर और कन्टेनर्स के परिवहन के लिए उपस्कर भी शामिल हैं) के प्रयोग, रख-रखाव या भाड़े के कारण उस राज्य में संदेय सकल राशि।

अनुच्छेद 12 के उपबन्ध ऊपर (ख) में उल्लिखित ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की आय का दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधान के प्रयोजनों के लिए निर्धारण करने में, किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" या "कलैण्डर

वर्ष", जैसा भी मामला हो, के लिए उस उद्यम को किसी भी हानि या मूल्यहास छूट के संबंध में स्वीकार्य कोई भी कटौती नहीं दी जाएगी।

#### अनुच्छेद 10

##### महयोगी उद्यम

जहां : —

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हैं जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं जैसीकि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, तो वहां ऐसा कोई लाभ, जो इन शर्तों के न होने की हानि में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु, उन शर्तों के कारण, उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद 11

##### लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लाभांश का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

- (क) लाभांश की सकल राशि का 15 प्रतिशत यदि हितभागी स्वामी ऐसी कम्पनी है जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी के शेयरों के कम से कम 25 प्रतिशत की स्वामी है;
- (ख) अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का 20 प्रतिशत।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय, शेयरों अथवा ऐसे अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ के भागीदार अण-दावे नहीं हों और अन्य नियमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही करा-धान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामलों में लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है। इस सन्दर्भ में, रूमानिया की संयुक्त कम्पनियों द्वारा पूंजी अभिदाताओं को वितरित किए जाने वाले लाभों को लाभांशों में मिला लिया जाता है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता है, और जिस धारणाधिकार के संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16, जैसी भी स्थिति हो, के उपबन्ध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरे राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां एक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हों अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है, वहां उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभसंबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

#### अनुच्छेद 12

##### ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।
2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार

सगाए गए कर की रकम ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के रहते हुए भी,—

(क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट होगी, बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में रखा जाता है :

(i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-मण्डल, कोई प्रशासनिक राज्यक्षेत्रीय एकक अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा

(ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक :

(ख) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि इसका हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो निम्नलिखित द्वारा दिए गए या समर्पित ऋण या उधार के संबंध में प्राप्त होता है :

(i) रूमानिया समाजवादी गणराज्य के वैका रूमाना डी कोमर्स एक्सटरेरिअर के मामले में उस सीमा तक जहां तक कि ऐसा ब्याज केवल निर्यात और आयात की वित्त-व्यवस्था करने में प्राप्त हुआ माना जा सकता हो ;

(ii) भारत के मामले में, भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्सिम बैंक) उस सीमा तक जहां तक कि ऐसा ब्याज केवल आयात और निर्यात वित्त व्यवस्था करने में प्राप्त हुआ माना जा सकता हो ;

(iii) संविदाकारी राज्य की कोई भी संस्था जो विदेश व्यापार में मार्बैजनिक् वित्त-व्यवस्था की प्रभारी संस्था हो ;

(iv) कोई भी अन्य व्यक्ति बशर्ते कि ऋण या उधार प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा स्वीकृत हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द में अभि-प्रेत है, प्रत्येक प्रकार के ऋण-दावों में प्राप्त आय, चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो या नहीं, और विशेषकर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बन्ध-पत्रों या ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बन्ध-पत्रों या ऋण-पत्रों से प्राप्त प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हैं । विलम्ब से की गयी अदायगी के लिए लगाया जाने वाला अर्थदण्ड इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए ब्याज नहीं माना जाएगा ।

5 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उत्पन्न होता हो, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाना हो, जिसमें अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से, स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पन्न करता हो, और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो । इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई प्रशासनिक राज्यक्षेत्रीय एकक, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । लेकिन, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, संविदाकारी राज्य में एक ऐसा स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गयी है, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7 जहां ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाला और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होनी, वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । इस प्रकार के मामले में अदा की गयी रकम का अनिश्चित भाग, इस अभिममय के अन्य उपबन्धों का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनी के अनुसार कर लगाने योग्य होगा ।

अनुच्छेद 13

कमीशन

3 एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले कमीशन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसे कमीशन पर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें यह उद्भूत होता हो, परन्तु इस प्रकार लगाया गया कर कमीशन की रकम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस परस्तीमा को लागू करने के तरीके को परस्पर सहमति से तय करेंगे ।



3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "कमीशन" शब्द का अभिप्राय है : किसी आदितिए, किसी सामान्य कमीशन अधिकर्ता अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को किया गया भुगतान, जो उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून द्वारा इस प्रकार के आदितिए या अधिकर्ता से सम्बद्ध हो जिसमें इस प्रकार का भुगतान उद्भूत होता हो ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे यदि कमीशन प्राप्तकर्ता का, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने में, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें कमीशन उद्भूत होता है, स्थायी संस्थापन है जिससे कमीशन उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 के उपबन्ध लागू होंगे ।

5. कमीशन एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तब समझा जाएगा जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक उप-मण्डल, कोई प्रशासनिक राज्यक्षेत्रीय एकक, कोई स्थानीय प्राधिकरण या राज्य का कोई निवासी हो । लेकिन, जहां कमीशन अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा स्थायी संस्थापन हो, जिसके संबंध में वह कार्यकलाप किए गए हों जिनके लिए कमीशन वहन किया जाता है और इस प्रकार का कमीशन उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता हो तो तब इस प्रकार का कमीशन उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है ।

6. जहां कमीशन अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी कमीशन की रकम, उस लेन-देन को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कमीशन की रकम अदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अतिम धर्जित रकम पर ही लागू होंगे । उस स्थिति में अदा की गयी रकम का अतिरिक्त भाग, इस अभिसमय के अन्य उप-बंधों का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगने योग्य होगा ।

#### अनुच्छेद 14

##### रायल्टी और तकनीकी सेवाओं

##### के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गयी रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे

उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 22.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टी" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कापीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें विनोद फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण में प्रयुक्त होने वाली फिल्मों अथवा टेप भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, व्यापारिक चिह्न, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव में संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है ।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद में प्रवर्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के लिए, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था शामिल है, प्रतिफल के रूप में, अदायगी करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्म-चारी को की गयी अदायगी से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी भी राशि की अदायगियों में अभिप्रेत है ।

5. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, और दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिनमें रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है, अथवा वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संप्रदा के संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 16 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टी और फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक उपमण्डल, कोई प्रशासनिक राज्यक्षेत्रीय एकक, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित

स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गयी फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जो इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा की गयी होती, तो वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी रकम के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

#### अनुच्छेद 15

##### पूँजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में यथाउल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण से एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति का एक हिस्सा है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें एक स्थायी संस्थापन (इकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों या वायुयानों जैसी पूँजीगत परिसम्पत्तियों से या ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के चलाने से संबंधित चल सम्पत्ति से उद्भूत होने वाले अभिलाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसमें उद्यम के कारगर प्रबन्ध का स्थान स्थित हो।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः एक संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. पैराग्राफ 1, 2, 3, और 4, में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी हो।

#### अनुच्छेद 16

##### स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के दूसरे स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय पर, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि उसकी दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की अवधि या अवधियाँ किसी संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" या "कैलेण्डर वर्ष" जैसी भी स्थिति हो, कुल 183 दिन अथवा उससे अधिक हो, तो आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलापों से उसे प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" शब्द में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकी, शल्य-चिकित्सकी, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

#### अनुच्छेद 17

##### पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि नियोजन इस प्रकार किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उससे प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर

केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता सगन "पूर्ववर्ती वर्ष" या "कैलेंडर वर्ष" में, जैसा भी मामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन में अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो; तथा
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक, किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा हवाई जहाजों के परिचालन के संबंध में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

### अनुच्छेद 18

निदेशकों की फीस और उच्च स्तरीय प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मण्डल के सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त की गयी निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी के उच्च स्तरीय प्रबंधकीय पद पर नियुक्त अधिकारी की हैसियत से प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

### अनुच्छेद 19

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 16 और 17 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में जैसे, कि थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार अथवा खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा अपने वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में अपनी इस प्रकार की हैसियत में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो,

तो ऐसे मामले में अनुच्छेद 7, 16 और 17 के उपबंधों के होते हुए भी, उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगेगा जिस राज्य में मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, किसी अन्य संविदाकारी राज्य में इस प्रकार किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उन कार्यकलापों को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिसमें उसके राजनीतिक उप-प्रभागों में से कोई भी उप-प्रभाग, प्रशासनिक क्षेत्रीय एकक अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, पूर्णतः अथवा अंशतः सहायता दी जाती है।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 16 और 17 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत से किसी संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त न होकर, किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती हो, ऐसे मामले में उस आय पर उस स्थिति में केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा, यदि उस अन्य व्यक्ति को दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से, जिसमें उसके राजनीतिक उप-प्रभागों में से कोई भी उप-प्रभाग, प्रशासनिक क्षेत्रीय एकक अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, पूर्णतः अथवा अंशतः सहायता दी जाती है।

### अनुच्छेद 20

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनीतिक उप-प्रभाग, प्रशासनिक क्षेत्रीय एकक अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग, एकक अथवा प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में पेंशन से भिन्न अदा किए गए पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में ही लगेगा।

(ख) तथापि ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में कर लग सकेगा; यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं है, जो :

- (1) उस राज्य का राष्ट्रिक हो; अथवा
- (2) सेवाएं अर्पित करने मात्र के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य को अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग, प्रशासनिक एकक अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में उस

राज्य अथवा उप-प्रभाग, एकक अथवा प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यष्टि को अथवा की गयी किसी भी पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा।

(ख) तथापि, यदि व्यष्टि उस अन्य राज्य का निवासी हो और राष्ट्रिक हो, तो केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में उस पेंशन पर कर लगेगा।

3. अनुच्छेद 17, 18, और 19 के उपबंध किसी, संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनीतिक उप-प्रभाग, किसी प्रशासनिक क्षेत्रीय एकक अथवा उनके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भलाए जा रहे कारोबार के संबंध में दी गयी सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

### अनुच्छेद 21

#### गैर सरकारी पेंशन और वार्षिकिया

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से अर्जित परन्तु अनुच्छेद 20 में उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न, किसी पेंशन अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा।

2. “पेंशन” शब्द का अर्थ उस नियतकालिक भुगतान से है, जो विगत समय में की गयी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोटों की क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया हो।

3. “वार्षिकी” शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए भुगतान किए जाने हेतु किसी वायित्व के अधीन जीवन पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित समय विधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

### अनुच्छेद 22

विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए भेजे गए विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. कोई व्यष्टि, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल-पूर्व संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और केवल इन कारणों से दूसरे संविदाकारी राज्य में अस्थायी तौर पर मौजूद रहता है:—

(क) उस दूसरे राज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय, महाविद्यालय, अथवा विद्यालय में एक छात्र रूप में; अथवा

(ख) एक व्यापारिक प्रशिक्षु के रूप में; अथवा

(ग) किसी धार्मिक, धर्मार्थ वैज्ञानिक अथवा शैक्षिक संगठन से अध्ययन के मूल प्रयोजनार्थ किसी

अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रूप में।

उस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके आगमन से छः वर्ष की अवधि तक उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित के संबंध में कर नहीं लगेगा:—

(i) उसके भरण-पोषण, शिक्षा, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए विदेश से प्राप्त धन-राशि;

(ii) अनुदान भत्ता अथवा पुरस्कार; और

(iii) विदेश से प्राप्त कोई पारिश्रमिक।

2. उपर्युक्त व्यष्टि द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य अपने भरण-पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए उस दूसरे राज्य में अपने आगमन से दो वर्ष की अवधि तक किसी रोजगार से प्राप्त आय पर यही छूट लागू होगी।

3. संविदाकारी राज्यों में से एक संविदाकारी के किसी ऐसे निवासी पर, जो उस दूसरे राज्य की सरकार अथवा किसी अधिकरण के साथ प्रबन्ध व्यवस्थाओं अथवा उनके किसी करार के अन्तर्गत केवल प्रशिक्षण, अध्ययन अथवा अनुस्थापना के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद हो, उसके द्वारा ऐसे प्रशिक्षण अथवा अध्ययन के लिए प्राप्त किए गए पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कर नहीं लगेगा।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए “मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय,” शब्दों का अर्थ है कोई ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय जो इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकरण द्वारा मान्यता-प्राप्त हो।

### अनुच्छेद 23

प्रध्यापक, अध्यापक और अनुसंधिस्त

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यालय, अथवा अन्य अनुमोदित संस्था में अध्यापन अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों प्रयोजनों के लिए उस दूसरे राज्य में जाने से तत्काल-पूर्व संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी हो अथवा था, इस प्रकार के अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए मिलने वाले किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में अपने आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।



2. यह अनुच्छेद शोध-कार्य से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि ऐसा शोध-कार्य प्राथमिक रूप से किसी व्यक्ति-विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 22 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी होना उस स्थिति में समझा जाएगा यदि वह "पिछले वर्ष" अथवा "कैलेंडर वर्ष", जैसा भी मामला हो, में उस राज्य का निवासी हो जिस वर्ष से वह दूसरे संविदाकारी राज्य में दोरे पर जाता है अथवा तत्काल पूर्ववर्ती "पिछले वर्ष" अथवा "कैलेंडर वर्ष" में दोरे पर जाता है।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्था" का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे इस संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

#### अनुच्छेद 24

##### अन्य आय

1. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें, जो जहाँ कहीं भी उद्भूत होंगी और जिनका उल्लेख इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेंगे।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुबंध 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित अच्छा सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं का निष्पादन करता है तथा जिस अधिकार या सम्पत्ति के संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 16, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उन मदों पर, जिन पर इस अभिसमय के पिछले अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते हों, उस दूसरे राज्य में कर लगेंगे।

#### अनुच्छेद 25

##### दोहरे कराधान का परिहार

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य में लागू कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान के नियमन के लिए जारी रहेंगे, सिवाय इसके कि जहाँ उक्त अभिसमय में निहित उपबंधों के विपरीत उपबंध बनाए जाते हैं।

2. भारत के किसी निवासी को रूमानिया में उद्भूत होने वाले ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत में तथा रूमानिया दोनों ही देशों में कर देना पड़ता है, रूमानिया के कानूनों के अधीन तथा इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा कटौती के माध्यम से संदेय रूमानिया कर की राशि को ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में संदेय भारतीयकर के प्रति जमा की जाने वाली एक राशि के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी जमा राशि उस भारतीय कर (इस प्रकार की कोई जमा राशि को स्वीकार किए जाने से पूर्व यथा-संगणित) से अधिक नहीं हो जो रूमानिया में उद्भूत लाभों अथवा आय के अनुरूप हो। इसके अलावा, जहाँ ऐसा निवासी कोई कंपनी है जो भारत में अतिकर जमा करता है, ऐसे मामले में उपर्युक्त जमा राशि प्रथमतः कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर के संदर्भ में मानी जाएगी और यदि कोई रकम शेष रहती हो तो उसके द्वारा भारत में देय अतिकर के संदर्भ में, जमा मानी जाएगी।

3. रूमानिया के किसी निवासी को भारत में उद्भूत होने वाले ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत तथा रूमानिया दोनों ही देशों में कर देना पड़ता है, भारतीय कानूनों के अंतर्गत तथा इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार, चाहे प्रत्यक्षतः अथवा कटौती के माध्यम से संदेय भारतीय कर की रकम को ऐसे लाभों अथवा आय के संबंध में संदेय रूमानिया कर के प्रति जमा की जाने वाली एक राशि के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी जमा-राशि उस रूमानिया कर (इस प्रकार की कोई जमा-राशि को स्वीकार किए जाने से पूर्व यथासंगणित) से अधिक न हो, जो भारत में उद्भूत लाभों अथवा आय के अनुरूप हो।

इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए रूमानिया राज्य उद्यमों द्वारा राज्य बजट को अदा किए गए लाभांश रूमानिया कर कहलाएंगे।

4. पैराग्राफ 3 में उल्लिखित जमा के प्रयोजनार्थ "देय भारतीय कर" शब्दों में ऐसी रकम को शामिल समझा जाएगा जो किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में संदेय थी परन्तु आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अंतर्गत प्रोत्साहन संबंधी विशेष उपायों के कारण उस वर्ष अथवा उस वर्ष के भाग के लिए कर में छूट अथवा कटौती के कारण, अदा नहीं की गई, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, अथवा जो



भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा उपबंधों के संशोधन के लिए या उसके अलावा एतस्मिन् पश्चात् लागू किए जा सकते हैं।

5. जहां इस अभिसमय के अंतर्गत किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय के संबंध में उस संविदाकारी राज्य से कर से छूट प्राप्त हो, तब ऐसे मामले में प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करने में कर की वही दर लागू कर सकता है जो इस अभिसमय के अनुसार कर से छूट दी गई आय को छूट न दिए जाने की स्थिति में लागू होती।

#### अनुच्छेद 26

##### सम-व्यवहार

(1) किसी संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में और शर्तों पर लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

(2) किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर ऐसा कराधान लागू नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही कार्य-कलापों में उन्हीं परिस्थितियों में और उन्हीं शर्तों के अंतर्गत प्रवृत्त उद्यमों पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

(3) इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उसने किसी संविदाकारी राज्य को, उस राज्य के अनिवामी व्यक्तियों को, कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की वैयक्तिक छूटे, राहतों, घटौतिया तथा कटौतिया प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कानून के तहत उस राज्य के केवल निवासी व्यक्तियों को ही उपलब्ध है।

4. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर वैसी ही परिस्थितियों में और शर्तों पर लागू होता है अथवा हो सकती है।

(5) इस अनुच्छेद से "कराधान" शब्द का अर्थ है वे कर, जो इस अभिसमय के विषय हैं।

#### अनुच्छेद 27

##### पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के होने हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह निवासी है। यह मामला, उस कार्य के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण इस अभिसमय के प्रतिकूल कराधान हुआ है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपात्त उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह कराधान के परिहार को मद्देनजर रखते हुए, जो अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। जो भी करार हो गया हो वह संविदाकारी राज्य के राष्ट्रीय कानूनों में निहित किसी सीमा के होने के बावजूद भी कार्यान्वित होगा।

3. अभिसमय के अर्थान्वयन में अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइया अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर सकेंगे जिनकी व्यवस्था अभिसमय में नहीं की गई है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय के अंतर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जहां कोई करार करने हेतु विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो वहां ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

#### अनुच्छेद 28

##### सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अभिसमय के उपबंधों को अथवा अभिसमय में शामिल करो से संबंधित संविदाकारी राज्यों के देशीय कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान अभिसमय के प्रतिकूल न हो, विशेष रूप से ऐसे करा की धोखाधड़ी अथवा उनके अपवर्धन को रोकने के लिए, आवश्यक ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त रखी जाएगी जैसे कि उस राज्य के देशीय कानूनों के अंतर्गत रखी जाती है। तथापि, यदि भेजने वाले देश में सूचना को मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो वह केवल उन व्यक्तियों

अथवा प्राधिकारियों (अदालतों और प्रशासनिक निकायों सहित) को प्रकट की जाएगी, जो करेंगे, जो अभिसमय के विषय है, के निर्धारण, उनकी वसूली, प्रवर्तन अथवा अभियोजन की कार्यवाही अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण के कार्यों में संलग्न है। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल इन्हीं प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे परन्तु अदालती कार्रवाई अथवा न्यायिक निर्णयों में इस सूचना को सार्वजनिक बना सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी कर-अपवंचन से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान सहित, जहां पर ऐसा करना उपयुक्त हो, उन मामलों से संबंधित उपयुक्त शर्तों, तरीके और तकनीक भी परामर्श के माध्यम से विकसित करेंगे जिनकी सूचना का विनिमय किया जाना है।

2 सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो तेजी तौर पर अथवा किसी मामले विशेष के सन्दर्भ में अनुरोध के आधार पर अथवा दोनों तरह से किया जायगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी तेजी आधार पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर समय-समय पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे।

3 पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का किसी भी हालत में यह अर्थ नहीं होगा कि किसी संविदाकारी राज्य को निम्न-लिखित कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए:—

- (क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक परिपाटी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जो उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो सकते;
- (ग) कोई ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सप्लाई करना जिसमें कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक भेद प्रकट हो जाए अथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया या सूचना सप्लाई करना, जिसका प्रकट किया जाना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो।

#### अनुच्छेद 29

##### कर-वसूली में सहयोग

1 संविदाकारी राज्य इस अभिसमय से संबंधित करेंगे की वसूली में उन मामलों में एक-दूसरे राज्य की मदद करने और समर्थन देने का जिम्मा लेते हैं, जहां अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार, कर निश्चित रूप से देय हैं।

2 वसूली के प्रवर्तन के किसी अनुरोध के मामले में किसी भी संविदाकारी राज्य के कर संबंधी बावों को, जिनका अन्तिम रूप से पता लगाया जा चुका है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रवर्तन के लिए स्वीकार किया जाएगा जिससे अनुरोध किया गया है; और उनकी वसूली उस राज्य

के करों के प्रवर्तन और उनकी वसूली हेतु लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी।

3 भारतीय कर के मामले में, अनुरोध-पत्र को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा रूमानिया समाजवादी गणराज्य के पास भेजा जाएगा, और उसके साथ वह प्रमाण-पत्र संलग्न होगा जैसा कि भारत के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करेंगे का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और करदाता द्वारा देय है।

4 रूमानिया कर के मामले में, अनुरोध पत्र को रूमानिया समाजवादी गणराज्य के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग के पास भेजा जाएगा और उसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न होगा जैसा कि रूमानिया के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करेंगे का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और करदाता द्वारा देय है।

5 जहां कर संबंधी दावे का उस संबंध में अपील किए जाने अथवा किसी अन्य कारण से अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं हुआ हो, वहां एक संविदाकारी राज्य, अपने राजस्व को बचाने के लिए, दूसरे संविदाकारी राज्य से उसके बारे में ऐसे अन्तरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत वैध हैं।

6 किसी करदाता से प्राप्त व्यक्तियों की वसूली में सहायता के लिए अनुरोध पत्र तभी पेश किया जाएगा जब अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस करदाता से कर वसूल करने के लिए उसकी पर्याप्त परिमत्पत्ति उपलब्ध न हो।

7 जिस संविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 5 के अनुसरण में कर वसूल किया जाता है, वह राज्य इस प्रकार वसूल की गयी रकम को तत्पश्चात् तुरन्त दूसरे संविदाकारी राज्य को भेजेगा, जिसने अनुरोध किया था, परन्तु ऐसे कर की वसूली में सहायता किए जाने के दौरान जो आवश्यक लागत आई है उसे वापिस पाने का हकदार होगा।

#### अनुच्छेद 30

##### राजनयिक और कौंसली कार्यकलाप

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत राजनयिक अथवा कौंसली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुच्छेद 31

## अभिसमय कर प्रवर्तन

1. इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों का आदान प्रदान बुखारेस्ट में किया जायगा।

2. यह अभिसमय, अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों का आदान प्रदान होने पर लागू होगा और इसके उपबंध निम्नलिखित पर प्रभावी होंगे :—

(क) भारत में, जिस केलेण्डर वर्ष में अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है, उस वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले पिछले वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

(ख) रूमानिया में, जिस केलेण्डर वर्ष में अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाता है, उस वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले पिछले वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान और जहाजों के संचालन करने वाले उद्यमों की आय के दोहरे कराधान के परिहार के लिए 25 सितम्बर, 1968 को हुआ विद्यमान करार इस अभिसमय के लागू होने पर समाप्त हो जाएगा।

## अनुच्छेद 32

## पर्यवसान

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के समाप्त होने के बाद से शुरु होने वाले किसी भी केलेण्डर वर्ष में जून के तीसवें दिन को या उससे पहले, राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को, अभिसमय के पर्यवसान का लिखित नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में इस अभिसमय का निम्नलिखित पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा :—

(क) भारत में, जिस केलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है, उसके अगले परवर्ती वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी पिछले वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में;

(ख) रूमानिया में, जिस केलेण्डर वर्ष में पर्यवसान का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती वर्ष में जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी केलेण्डर वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधो-हस्ताक्षरकर्तियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ सत्तासी के मार्च माह के दसवें दिन को, हिन्दी रूमानिया और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया। इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इन पाठों में से किसी के बीच भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

(ह. ब्रह्म दत्त)

(ह. डिमिट्री अन्कूटा)

भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से

रूमानिया समाजवादी गणराज्य  
की सरकार की ओर से

[फा. सं. 501/4/76—एफ टी डी]

पी. के. अप्पचू, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 8th February, 1988

NOTIFICATION NO. 7754

## INCOME TAX

G.S.R. 80(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Romania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 14th November, 1987 on the exchange of the Instruments of Ratification by both the contracting States, as required by paragraph 1 of Article 31 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

## ANNEXURE

## CONVENTION

## BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

## AND

THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA

## FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Romania desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and to promote and strengthen the economic relations between the two countries on the basis of equality in rights and reciprocal advantage.

Have Agreed as Follows :

## Article 1

## PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both the Contracting States.

## Article 2

## TAXES COVERED

1. The taxes to which this Convention shall apply are :

(a) In the case of India :

(1) Income-tax and any surcharge thereon; and

(2) Sur-tax;

(hereinafter referred to as 'Indian tax').

(b) In the case of Romania :

(1) the tax on incomes derived by individuals and corporate bodies;

(2) the tax on the profits of joint companies constituted with the participation of some Romanian economic organisations and some foreign partners; and

(3) the tax on income realised from agricultural activities;

(hereinafter referred to as 'Romanian tax'),

371 GI/88-3

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1.

3. The competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which are made in their respective taxation laws which are the subject of this Convention and furnish copies of relevant enactments and regulations.

## Article 3

## GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air space above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;

(b) the term "Romania" used in a geographical sense, means the territory of the Socialist Republic of Romania including the territorial sea and the continental shelf as well as any other area beyond the territorial waters of Romania where Romania exercises sovereign rights, in accordance with the international law and with its own law concerning the exploration and exploitation of the natural, biological and mineral resources existing in the sea, waters, seabed and subsoil of these waters;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Romania as the context requires;

(d) the term "tax" means Indian tax or Romanian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;

(e) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(f) the term "company" means any body corporate, including a joint company which is incorporated under the Romanian law or any entity which is treated as a company under the taxation laws of the respective Contracting States;

(g) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "competent authority" means in the case of India the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative, and in the case of Romania the Ministry of Finance or its authorised representative;

(i) the term "national" means :

— in the case of India, any individual possessing the nationality of India and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in India;

— in the case of Romania, any individual possessing the citizenship of Romania and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in Romania;

(j) the term "a political subdivision" means a political subdivision in India;

(k) the term "an administrative territorial unit" means an administrative territorial unit in Romania;

(l) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

#### Article 4

##### FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who is a resident of that State in accordance with the taxation laws of that State.

2. Where by reason of the provision of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States then his residential status for the purposes of this Convention shall be determined in accordance with the following rules :—

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he

has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");

(b) If the Contracting States in which he has his centre of vital interests cannot be determined or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

#### Article 5

##### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on

2. The term "permanent establishment" includes especially :

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

— (h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;

(i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;



- (j) an installation or structure used for the exploration of natural resources;
- (k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity (together with other such sites, projects or activities, if any) continues for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery or equipment.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise;
- (f) the selling of goods or merchandise belonging to the enterprise displayed in an occasional temporary fair or exhibition in the process of closing down of such fair or exhibition;
- (g) project or supervisory activity, being incidental to sale of machinery or equipment, carried on by an enterprise other than the seller of machinery or equipment and not continuing for a period exceeding six months.

However, the provisions of sub-paragraphs (a) to (g) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said sub-paragraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise

of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if :

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control as, that enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carried on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control as, that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carried on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

## Article 6

### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed only in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term 'immovable property' shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

#### Article 7

##### BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits, which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of

actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Article 8

##### AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

#### Article 9

##### SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, such profits may also be taxed in the other Contracting State if the shipping activities connected

with the operation of ships in international traffic are carried on in that other State, but the tax so charged shall not exceed 2.50 per cent of the gross amount payable in respect of operation of ships in that other State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.

4. For the purposes of this Article, the gross amount payable in respect of operation of ships in a Contracting State shall mean the aggregate of the following amounts, namely :

- (a) the gross amount payable on account of carriage of passengers, livestock, mail or goods shipped at a port or ports in that Contracting State;
- (b) interest arising in that Contracting State on funds connected with the operation of ships in international traffic; and
- (c) the gross amount payable in that State on account of the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment of the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

The provisions of Article 12 shall not apply in relation to interest referred to in (b) above.

5. In determining the income of an enterprise of a Contracting State for the purposes of taxation in the other Contracting State, no deduction shall be allowed in respect of any loss or depreciation allowance admissible to that enterprise for any earlier "previous year" or "calendar year", as the case may be.

## Article 10

### ASSOCIATED ENTERPRISES

#### Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then only profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

## Article 11

### DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. In this context, the profits distributed by Romanian Joint Companies to the capital subscribers are assimilated to dividends.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profit or income arising in such other State.



## Article 12

## INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, —

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by —

(i) the Government, a political sub-division, an administrative territorial unit, or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracting State and is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :

(i) in the case of Socialist Republic of Romania, BANCA ROMANA DE COMERT EXTERIOR to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;

(ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India (Exim Bank), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;

(iii) any institution of a Contracting State in charge of public financing of external trade;

(iv) any other person provided that the loan or credit is approved by the Government of the first-mentioned Contracting State;

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. **Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.**

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself a political sub-division, an administrative territorial unit, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

## Article 13

## COMMISSION

1. Commission arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such commission may be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the amount of the commission. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "commission" as used in this Article means a payment made to a broker, a general commission agent or to any other person assimilated to such a broker or agent by the taxation law of the Contracting State in which such payment arises.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the commission, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the commission arises a permanent establishment with which the activity giving rise to the commission is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Commission shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, an administrative territorial unit, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the commission, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the activities for which the payment is made was incurred, and such commission is borne by such permanent establishment, when such commission shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the commission, having regard to the transaction for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

#### Article 14

##### ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 22.5 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, an administrative territorial unit, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being to the other provisions of this Convention.

#### Article 15

##### CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains



from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains arising from a capital asset being ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

#### Article 16

##### INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "calendar year", as the case may be, in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

#### Article 17

##### DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 18, 19, 20, 21, 22 and 23 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is

so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "calendar year", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad on a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

#### Article 18

##### DIRECTORS' FEES AND REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

#### Article 19

##### ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 16 and 17, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 16 and 17, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal

activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions, administrative territorial units or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and Articles 7, 16 and 17, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions, administrative territorial units or local authorities.

#### Article 20

#### REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, a political sub-division, an administrative territorial unit or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, sub-division, unit or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State, a political sub-division, an administrative territorial unit or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, sub-division, unit or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 17, 18 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, a political sub-division, an administrative territorial unit or a local authority thereof.

#### Article 21

#### NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 20, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other

Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

#### Article 22

#### STUDENTS, APPRENTICES AND PERSONS SENT FOR SPECIALISATION

1. An individual who is or was resident of one of the other Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State solely :

- (a) as a student at a recognised university, college or school in that other State; or
- (b) as a business apprentice; or
- (c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study from a religious, charitable, scientific, or educational organisation;

shall be exempt from tax in that other State for a period of six years from his arrival in that other Contracting State in respect of—

- (i) the remittance from abroad for the purposes of his maintenance, education, study or training;
- (ii) the grant, allowance or award; and
- (iii) any remuneration from abroad.

2. The same exemption shall apply to income derived by the above-mentioned individual from an employment which he exercises in the other Contracting State in order to supplement his means for maintenance, education, training and other expenses for specialisation, for a period limited to two years from his arrival in that other State.

3. A resident of one of the Contracting States present in the other Contracting State under arrangements with the Government of that other State or any agency or instrumentality thereof solely for the purpose of training, study or orientation shall be exempt from tax for a period not exceeding two years from his arrival in that other Contracting State in respect of remuneration received by him on account of such training or study.

4. For the purposes of paragraph 1, the term "recognised university, college or school" means a university, college or school which has been recognised in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

## Article 23

## PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 22, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "calendar year", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "calendar year".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

## Article 24

## OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

## Article 25

## AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in the Convention.

2. The amount of Romanian tax payable, under the laws of Romania and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of profits or income arising in Romania, which has been subjected to tax both in India and in Romania, shall be allowed as a credit against Indian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in Romania. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

3. The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Romania, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and in Romania, shall be allowed as a credit against Romanian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed Romanian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in India.

For the purposes of this paragraph, profits paid by the Romanian State enterprises to the State budget shall be deemed to be Romanian tax.

4. For the purposes of the credit referred to in paragraph 3, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any assessment year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof by the special incentive measures under the provisions of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), which are designed to promote economic development, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting economic development in India.

5. Where under this Convention a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Convention had not been so exempted.



## Article 26

## NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation, and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not residents in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

## Article 27

## MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

## Article 28

## EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection, the enforcement of prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

#### Article 29

#### ASSISTANCE IN COLLECTION

1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Convention relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the State making the request.

2. In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its taxes.

3. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, to the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Romania and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

4. In the case of Romanian tax, the request will be sent by the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Romania to the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, in India and will

be accompanied by such certificate as is required by the laws of Romania to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

5. Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of any reasonable costs incurred in the course of rendering assistance in the recovery of such tax.

#### Article 30

#### DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges and diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

#### Article 31

#### ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Bucharest.

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provision shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the instruments of ratification are exchanged;
- (b) in Romania, in respect of income arising in any calendar year beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the instruments of ratification are exchanged.



3 The existing Agreement for the avoidance of double taxation of income of enterprises operating aircraft and ships in international traffic dated the 25th September, 1968 shall cease to have effect upon the entry into force of this Convention.

### Article 32

### TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirteenth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given;

- (b) in Romania, in respect of income arising any calendar year beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at New Delhi this 10th day of March one thousand nine hundred and eighty seven in the Hindi, Romanian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence amongst the three texts, the English text shall be the operative one.

Sd/- Brahm Dutt  
For the Government of  
the Republic of India

Sd/- Dimitrie Ancuta  
For the Government of the  
Socialist Republic of Romania.  
[F. No. 501/476-FTD]  
P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

